जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 350 प्रभात चूरू, शनिवार 19 अप्रैल, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के लिये विदाई भोज की तैयारी आरंभ होने लगी है

इस घटनाक्रम से यह आकलन लगाया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में नए भाजपा अध्यक्ष का चयन पूरा हो जायेगा

- आरएसएस यह चाहता है कि नया अध्यक्ष ऐसा मजबूत व्यक्ति हो, जो सख्त निर्णय ले सके और किसी के दबाव में झुके नहीं।
- दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न संघ के समक्ष है कि क्या मोदी 75वां जन्मदिन मनाने के बाद रिटायर होंगे तथा उनके रिटायरमैंट के बाद उनकी जगह कौन लेगा और देश के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की गद्दी पर कौन बैठेगा।
- आरएसएस इस बात से भी काफी चिंतित है कि भाजपा से जो बहुत से युवा पहली बार जुड़े हैं, क्या वे संघ की संस्कृति में अच्छी तरह समावेश हो गये हैं।
- भाजपा के बड़े नेता इस बात पर आश्वस्त हैं, पर फिर, भाजपा व संघ परिवार दोनों चाहते हैं कि आरएसएस का पुराना कार्यकर्ता, जो संघ की संस्कृति में डूबा हुआ है तथा ओतप्रोत है, वही पार्टी का नया अध्यक्ष होना चाहिये।
- इन मुद्दों पर मूल सहमति नहीं बन पाई है अभी तक तथा ये गतिरोध खत्म करने के लिये सभी प्रयासरत हैं।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। भाजपा-आरएसएस ने भाजपा-अध्यक्ष के चयन के अंतिम निर्णय की प्रक्रिया तेज कर दी है, क्योंकि यह मुद्दा लम्बे समय से खिंचता चला आ रहा है और इससे ऐसा संदेश जा रहा है कि पदमुक्त होने जा रहे पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के स्थानापन्न के मामले में संघ परिवार के अंदर कोई बड़ा मतभेद है।

सूत्रों का कहना है कि नड्डा के विदाई समारोहों की श्रंखला शुरु हो गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नये पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति चन्द रोज़ में ही हो जायेगी।

सूत्रों का कहना है कि आरएसएस के मन में कुछ महत्वपूर्ण चिन्ताएं हैं, जिनका समाधान नये पार्टी अध्यक्ष के चयन एवं नियुक्ति से पहले होना जरुरी है। आरएसएस इस पद के लिये एक ऐसा ताकतवर और दृढ़ नेता चाहती है, जो किसी के भी आगे झुके नहीं, बल्कि मुद्दों के मामले में दृढ़ रहे तथा कठोर निर्णय ले सके।

कई सवाल हैं, जैसे सितम्बर में 75 साल के हो जाने पर, नरेन्द्र मोदी पद-त्याग के लिये सहमत होंगे या नहीं?

मोदी के सेवानिवृति होने की स्थिति में, उनके स्थान पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा?

देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा?

देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा?

लेकिन आरएसएस के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा नई नस्ल के उन नेताओं का है, जो अन्य पार्टियों से भाजपा में लिये गये है, और क्या वे नेता संघ-संस्कृति के साथ एकाकार हो गये हैं।

भाजपा की संस्कृति से अपरिचित ऐसे नेताओं को लेकर आरएसएस के अंदर बहुत अधिक बेचैनी है।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का फोकस बूथ-लैवल कमेटियों तथा जमीनी कार्यकर्ताओं से सम्पर्क जैसी पार्टी की असली सम्पत्तियों पर है और उनका कहना है कि भाजपा नेताओं की नई खेप इसके प्रति सजग एवं इससे परिचित है तथा वह पार्टी को संभाल सकती है।

लेकिन भाजपा का कहना है कि यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लायसैंस नहीं है तो राजापार्क के रैस्त्रां बंद करो

जयपुर, 18 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर को निर्देश दिए हैं कि याचिका में पक्षकार बनाए गए 9 रेस्त्रां के पास यदि लाइसैंस नहीं है तो उनका आगामी सुनवाई तक संचालन रोका जाए। चीफ जस्टिस एम.एम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश शालिनी श्रीवास्तव व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में बताया कि शहर में संचालित कई रेस्त्रां और अन्य प्रतिष्ठान नगर निगम की ओर से दिए जाने वाले

- हाई कोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर को निर्देश दिये, अगली सुनवाई तक बिना लायसैंस वाले रैस्त्रां का संचालन रोकें।

लाइसैंस के बिना ही खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। जिसके चलते आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस संबंध में नगर निगम को कई बार शिकायत भी दी गई, लेकिन अभी तक निगम प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता की ओर से शहर के राजा पार्क क्षेत्र में संचालित 9 रेस्त्रां संचालकों को पक्षकार भी बनाया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि यदि इन 9 रेस्त्रां के पास निगम का लाइसैंस नहीं है तो अंतरिम रूप से उनका संचालन रोका जाए।

प्र.मंत्री मोदी ने एलन मस्क से टेलीफोन मिलाकर बात की

बातचीत का मुद्दा, मस्क की सैटलाइट पर आधारित संचार सेवा, स्टारलिंक को भारत में पैर पसारने की इजाज़त देना लगता है

- प्र.मंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैण्डल पर यह जानकारी जनता से शेयर की।
- वैसे भी मोदी, मस्क से अपनी पिछली वॉशिंगटन यात्रा के दौरान मिले थे और उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शुक्रवार को स्टारलिंक के उच्चाधिकारियों, वाइस प्रेसिडेन्ट चैड गिब्स व वरिष्ठ निदेशक रायन गुडनाइट से मिले। स्टारलिंक को भारत सरकार से शीघ्र ही अनुमति मिलने की संभावना है।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मस्क की इलैक्ट्रिक कार टैस्ला को कैनडा व फिर इंगलैंड में इलैक्ट्रिक व्हिकल रिबेट मिलने की संभावना नहीं है। अतः मस्क भारत में टैस्ला कार बनाने के लिये फैक्टरी लगाने की फिराक में भी हैं। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल व वोडाफोन आइडिया भी भारत में मस्क से कोलैबोरेशन करके स्टारलिंक सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश में हैं।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। हाल की घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के खतरे, भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस के लाँच की योजनाओं में बाधा नहीं बनेंगे।

उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की, स्टारलिंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मस्क को फोन किया। यह बातचीत टैक्नॉलजी और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर केन्द्रित थी। इस वर्ष के शुरु में मोदी और मस्क की वॉशिंगटन में आमने-सामने मुलाकात हो चुकी है। अपनी इस टेलिफोन बातचीत के बाद मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "एक्स" पर लिखा, "मस्क से टैक्नॉलजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर बात की। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने् के लिए प्रतिबद्ध है।"

मोदी के इस फोन कॉल को उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, जिसमें मस्क की कंपनी टैस्ला भारत में मैनुफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का प्रयास कर रही है। वहीं, रिलायंस जिओ ने, भारत में स्टारलिंक की हाईस्पीड सैटेलाइट इन्टरनैट सेवाएं शुरु करने के लिए स्पेसएक्स के साथ पार्टनशिप की है। स्पेसएक्स भारत में अधिकारिक रुप से स्टारलिंक सेवाएं देने के लिए सरकारी मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है।

हालांकि, हाल के हफ्तों में, टैरिफ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बाँग्लादेश, मुर्शिदाबाद के दंगों को भुनाने की कोशिश में!

बाँग्लादेश ने भारत को सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देकर याद दिलाया, मुसलमानों की सुरक्षा व हिफाज़त, भारत की जिम्मेवारी है

- ममता बनर्जी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, यह हिंसा बीएसएफ ने फैलायी है।
- बंगाल की मु.मंत्री के अनुसार, बीएसएफ ने बच्चों को पैसे देकर उकसाया, पत्थर व मिसाइल दागने के लिये, क्योंकि अब दंगाग्रस्त इलाके में बीएसएफ की जिम्मेवारी है, पश्चिम बंगाल सरकार दोषमुक्त है।
- ममता ने जनता का ध्यान बांटने के लिये, पुरानी चाल चली और आरोप लगाया कि दंगे सुनियोजित हैं तथा अमित शाह की योजना के अंतर्गत हुए हैं।
- एक और "अनकनैक्टेड" बात जोड़ी कि अमित शाह का क्या होगा, मोदी के जाने के बाद।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। बाँग्लादेश बंगाल में विस्फोटक साम्प्रदायिक तनाव को और बड़ा और विकृत रुप देने की कोशिश में हैं। इस पड़ोसी देश ने भारत को मुस्लिमों की सुरक्षा एवं संरक्षण की याद दिलाने वाले सार्वजनिक बयान देना शुरु कर दिया है।

यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि बाँग्लादेश ने सीमावर्ती जिले में कुछ जिहादी तथा उग्रवादी भेजे थे तथा तनाव को पूरी सक्रियता के साथ उकसा रहा था। अब बाँग्लादेश अपनी इस सक्रिय दखलंदाजी को छिपाने के लिये हमारा ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है।

मुर्शिदाबाद तथा बंगाल के अन्य जिलों में साम्प्रदायिक हिंसा के तुरंत बाद आई टिप्पणी तथा बाँग्लादेश के हस्तक्षेप को लेकर, भारत सरकार ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बाँग्लादेश के अधिकारियों से कहा है कि वे अपना काम करें तथा वहाँ अल्पसंख्यक हिन्दुओं की सुरक्षा करें।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के तुरंत बाद, बाँग्लादेश में बड़े पैमाने में अग्निकांड एंव हिंसा की घटनाएं हुई थीं। दुर्भाग्य की बात यह हुई कि उस राजनैतिक हिंसा ने शीघ्र ही देश में हिन्दू समुदाय के प्रति नफरत के एक सूत्रीय कार्यक्रम का रुप ले लिया था।

बाँग्लादेशी हिन्दुओं के खिलाफ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूनेस्को के "मैमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर" में गीता, नाट्यशास्त्र शामिल

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने दुर्लभ अभिलेखों की अपनी सूची, "मैमरी ऑफ द वर्ल्ड" रजिस्टर में गीता और भरत मुनि के नाट्ययशास्त्र को भी शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने

- प्रधानमंत्री ने इसे हर भारतीय के लिये गर्व की बात बताया। इस सूचि में अब भारत के दर्ज अभिलेखों की संख्या 14 हो गई।

इसकी प्रशंसा की और इसे दुनिया भर में रह रहे भारतीयों के लिए गर्व की बात बताया। इसके साथ ही इस सूची में भारत के दर्ज प्राचीन अभिलेखों की संख्या 14 हो गयी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 'भारत की सभ्यतागत विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने यूनेस्को के निर्णय के बारे में संस्कृति मंत्री शेखावत के एक पोस्ट पर टिप्पणी में, लिखा, समूचे विश्व में प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण। गीता और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उप मु.मंत्री एकनाथ शिंदे, अमित शाह से मिले, पर इससे उनकी कमज़ोरी ही जाहिर हुई

म्युनिसिपल चुनाव से पूर्व, एकनाथ शिंदे काफी हिले हुए हैं क्योंकि उन्हें शिव सेना के उद्धव ठाकरे खेमे व भाजपा गठबंधन के अन्य घटकों से एक साथ संघर्ष करना पड़ रहा है

- भाजपा ने अप्रत्यक्ष संकेत दिया है कि वो घटकों के आपसी संघर्ष में एनसीपी (अजित पंवार) के पक्ष में हैं। यह भाजपा का, महाराष्ट्र की राजनीति की दृष्टि से बुद्धिमतापूर्ण कदम है, पर, शिंदे के लिये खतरे की घंटी है।
- शिंदे ने मुम्बई में 13 अप्रेल को सहयाद्री गेस्ट हाउस में बात करके, शिव सेना को तोड़ने में अपनी भूमिका याद दिलाई तथा अमित शाह से हस्तक्षेप करने की दुहाई दी। मगर, शाह पर इस दुहाई का खास असर होता नहीं दिख रहा है, तो क्या महायुति गठबंधन टूट भी सकता है?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। हाल ही में, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे तथा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बीच हुई गोपनीय मीटिंग से राज्य में सत्तारुढ़ "महायुति" गठबंधन की दरारों के गहरी होने की व्यापक अटकलें लगाई जा रही है। ज्ञातव्य है कि राज्य के म्यूनिसिपल चुनाव होने में कुछ सप्ताह ही शेष हैं। तेरह अप्रैल को मुम्बई के सहयात्री गैस्ट हाउस में हुई इस मीटिंग ने गठबंधन की एकता को लेकर चिन्ताएं बढ़ा दी हैं। फन्ड्स तथा राजनैतिक पदों को लेकर पैदा हुये अन्दरुनी विवादों से सत्तारुढ़ गठबंधन के स्थायित्व के लिये खतरा पैदा हो गया है।

महायुति गठबंधन, जिसमें शिवसेना (शिन्दे गुट) भारतीय जनता पार्टी तथा नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-अजित पवार गुट) शामिल हैं, 2024 के हलचलपूर्ण विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता में आया था। इसका गठन 2022 में शिव सेना के नाटकीय रुप से टूटने के बाद हुआ था, जब शिन्दे ने उद्धव ठाकरे का नेतृत्व अस्वीकार कर दिया तथा महाविकास अघाड़ी सरकार को सत्ता से हटाने के लिये भाजपा से गठजोड़ कर लिया था।

इस पार्टनरशिप ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस की सत्ता में वापसी तो हो गई थी, लेकिन शिन्दे गुट का अपने मित्र दलों के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा है और उनका असंतोष बढ़ता ही जा रहा है, और उनका यह तनाव शाह के साथ हाल ही हुई उनकी मीटिंग से खुलकर सामने आ गया है। सूत्रों का कहना है कि संसाधनों के आवंटन तथा राजनैतिक महत्व से सम्बंधित शिकायतों के समाधान के लिये शिन्दे ने शाह का हस्तक्षेप की मांग की है। इस विवाद का मुख्य कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों का वितरण है, जिस पर एन.सी.पी. नेता अजित पवार का नियंत्रण है। शिंदे ग्रुप का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है।

एक और विवादास्पद मुद्दा रायगढ़ जिले के संरक्षक मंत्री का पद है, जो आर्थिक और चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। शाह के, एन.सी.पी. नेता सुनील तटकरे के घर जाने से इस धारणा को और बल मिला है कि भाजपा इस पद के लिए तटकरे को प्राथमिकता दे रही है, जिससे शिंदे गुट स्वयं को हाशिए पर महसूस कर रहा है और इसे लेकर गुट में नाराज़गी बढ़ रही है। नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में ये मतभेद महंगे साबित हो सकते हैं। ये चुनाव महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में गठबंधन की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बाइस नक्सलियों ने सामूहिक आत्म समर्पण किया

सुकमा, 18 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 40.5 लाख रुपये के 12 इनामी माओवादी सहित 22 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष शुक्रवार को सामूहिक रुप से आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में नौ महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन नक्सलियों ने एक साथ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

- इन नक्सलियों में से 12 पर 40 लाख रुपये का ईनाम था।

(सीआरपीएफ) के अफसरों के सामने सरेंडर किया है। इन पर कुल 40 लाख रुपये का इनाम घोषित है। ये सभी नक्सली माड़ डिवीजन (छत्तीसगढ़) और नुआपाडा डिवीजन (ओडिशा) में सक्रिय रहे हैं। आज एक साथ सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक दंपति भी शामिल हैं। इन पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम घोषित है। इनके सरेंडर को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका तीन सप्ताह में ही, जल्दी से जल्दी, भारत के साथ व्यापारिक समझौता फाइनल कर लेना चाहता है

अमेरिका का मकसद केवल "टैरिफ" में भारत के पक्ष में कुछ व्यवहारिक कमी करना ही नहीं है, बल्कि, चीन की एशिया व विश्व में व्यापारिक धौंस पर अंकुश लगाना है

- अमेरिका चाहता है, भारत से "बायलेटरल" व्यापारिक समझौता करके पैसिफिक देशों (साउथ कोरिया, वियतनाम, ताईवान, आस्ट्रेलिया व जापान) से व्यापारिक अरैंजमैंट को फाइनल करे।
- उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। उन्होंने एक इन्टरव्यू में कहा कि भारत पर वैसे भी "टैरिफ की मार" नहीं पड़नी चाहिये, क्योंकि भारत तो "टैरिफ वॉर" के बहुत पहले से ही अमेरिका से "बायलेटरल" व्यापारिक समझौते की बात कर रहा था।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। तेजी से बदलते वैश्विक ट्रेड ड्रामा में भारत एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में उभरा है क्योंकि अमेरिका अपने अन्य मित्र देशों की तुलना में भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमैंट करने के लिए जल्दबाजी में है। इसमें टैरिफ रेट के अलावा और भी बहुत कुछ दांव पर है। इस डील से इंडो पैसेफिक इकॉनमिक ऑर्डर में भारत की स्थिति पुनः परिभाषित हो सकती है और चीन के वैश्विक दबदबे को नियंत्रित करने के लिए यू एस के नेतृत्व वाली रणनीति को प्रोत्साहित करेगा।

पता चला है कि भारत, जापान दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ डील करने के लिए वाइट हाउस रात-दिन एक कर रहा है, इसके लिए उसने तीन सप्ताह की समय सीमा रखी है। ये उच्चस्तरीय वार्ताएं असल में वैश्विक बाज़ार में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने और ट्रेड कॉरिडोर को नया आकार देने के विस्तृत भू-राजनैतिक प्रयासों का अंग हैं।

इस डिप्लोमैटिक उथल-पुथल की शुरुआत अमेरिका द्वारा टैरिफ की घोषणा करने से हुई थी। लेकिन टैरिफ पर 90 दिन की रोक ने देशों को व्यक्तिगत ट्रेड डील्स करके और दण्डात्मक शुल्क से बचने का एक छोटा सा मौका दिया है।

भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा है। वॉशिंगटन के साथ कई महीनों से चल रही उच्च स्तरीय वार्ता के बावजूद भारत को ट्रंप की नई टैरिफ लिस्ट में शामिल किया गया और भारतीय सामान पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया। यह रेट दक्षिण कोरिया के समकक्ष है, पर वियतनाम व ताईवान से कुछ कम है। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक इंटरव्यू में बताया कि टैरिफ की धमकी से बहुत पहले से ही भारत द्विपक्षीय वार्ताएं कर रहा है। भारत उन देशों में नहीं था, जिन पर वास्तव में टैरिफ लगाने की जरुरत थी, क्योंकि हम पहले से ही द्विपक्षीय वार्ताएं कर रहे थे।"

चीन के विपरीत, भारत ने शांत और व्यवहारिक रास्ता अपनाया। जहाँ चीन ने भी बदले में आक्रामक टैरिफ लगाए और निर्यात पर नियंत्रण किया, वहीं नई दिल्ली ने बैक चैनल डिप्लोमैसी और वार्ता का सहारा लिया। इसी बीच अमेरिका ने भारत के साथ डील को प्राथमिकता दी और अमेरिका, ब्रिटेन के साथ अपनी बहुप्रतीक्षित संधि से पहले भारत के साथ डील को फाइनल कर लेगा। यह तत्परता ट्रम्प प्रशासन की रणनीतिक प्राथमिकता को दर्शाती है, जिसमें वह अपने इंडोपैसेफिक सहयोगियों के साथ व्यापारिक समझौते करने की दिशा में काम कर रहा है।

नई दिल्ली के व्यापारिक वार्ताएं सिर्फ टैरिफ से छूट के लिए ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक हैं। भारत जैनरिक दवाओं के निर्यात, आईटी सेवाओं और ई-कॉमर्स, जहाँ भारतीय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो हजार से ऊपर के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी नहीं

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और ऐसे किसी भी प्रस्ताव की बात भ्रामक और निराधार है।

बयान में कहा गया है कि कुछ

- वित्त मंत्रालय ने कहा इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपकरणों (कार्ड जैसे माध्यमों) का उपयोग करके किए गए भुगतानों से संबंधित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जैसे शुल्कों पर ही जीएसटी लगाया जाता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) 30 दिसंबर 2019 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) को यूपीआई के माफित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK